www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 04 | अंक – 224 | जौनपुर शनिवार, 04 अप्रैल 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय पर पुलिस बल तैनात करने की मांग

चंडीगढ़, (एजेंसी)। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय पर पुलिस बल तैनात करने की मांग की है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर सुरक्षा का हवाला दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया एवं कार्यालय प्रभारी संजीव भारद्वाज ने शुक्रवार को हरियाणा पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र मीडिया में जारी करते हुए बताया कि चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर बम धमाका हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियां अभी इस मामले की जांच कर रही हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा व पंजाब के राजनीति दलों के मुख्यालय हैं। इनके बाहर अक्सर पुलिस की गश्त रहती है और पुलिस बल तैनात रहता है। दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सेक्टर नौ स्थित मुख्यालय की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित है। संजीव भारद्वाज के अनुसार, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अक्सर चंडीगढ़ के सेक्टर नौ स्थित मुख्यालय में रहते हैं। प्रदेश में भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। राव नरेंद्र द्वारा जिलों में कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें चंडीगढ़ तथा हरियाणा में पुलिस की पायलट जिप्सी का कवर प्रदान किया जाए तथा एचपीसीसी मुख्यालय की सुरक्षा को मजबूत करते हुए यहां पुलिस बल तैनात किया जाए। इसके अलावा समय–समय पर पुलिस के बम निरोधक दस्ते, डॉग स्कवायड आदि की जांच को यकीनी बनाया जाए।

सरकार ने फ्लाइट में 60 प्रतिशत मुफ्त सीट चयन अनिवार्य करने वाले आदेश को किया स्थगित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने फ्लाइट में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के देने के अपने पहले के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जो 20 अप्रैल से लागू होने वाला था। नागर विमानन मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को भेजे गए एक पत्र में कहा कि इस फैसले की समीक्षा की गई है। यह समीक्षा फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद की गई, जिसमें इस नियम के ऑपरेशनल और कमर्शियल असर को लेकर सवाल उठाए गए थे। एयरलाइंस ने कहा था कि यह नियम किराया ढांचे को प्रभावित कर सकता है और मौजूदा डिरेगुलेटेड टैरिफ सिस्टम के अनुरूप नहीं है। सरकार ने कहा कि इन सभी पहलुओं को देखते हुए और मामले की विस्तृत समीक्षा होने तक 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त देने का प्रावधान फिलहाल अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में, फ्लाइट की 20 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बुक की जा सकती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए यात्रियों को शुल्क देना पड़ता है। एयरलाइंस आमतौर पर सीट चयन के लिए 200 रुपए से लेकर 2,100 रुपए तक चार्ज करती हैं, जो सीट की लोकेशन और अतिरिक्त लेगरूम जैसी सुविधाओं पर निर्भर करता है।

जीवन और व्यापार आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राज्यसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) बिल, 2026 पारित किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता और व्यापार के लिए एक बड़ी सफलता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह बिल नागरिकों के लिए विश्वास आधारित प्रणाली को मजबूत करता है और पुराने नियमों और कानूनों को खत्म करने का काम करता है। इस बिल से मामलों का तेजी से निपटारा होगा और छोटे अपराधों को अपराध के दायरे से बाहर करके मुकदमों का बोझ कम होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर

पोस्ट में पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिल तैयार करने में संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई और सभी सुझावों को ध्यान में रखा गया। बता दें कि गुरुवार को राज्यसभा में इस बिल के माध्यम से 79 केंद्रीय कानूनों में 784 प्रावधानों में संशोधन किया है, ताकि छोटे अपराधों को सरल बनाया जा सके, व्यापार और जीवन दोनों को आसान बनाया जा सके और लोगों के उत्पीड़न पर रोक लगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) बिल, 2026 पारित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संसद में जन विश्वास बिल 2026 का पारित होना भारत के लिए जीवन और व्यापार को सरल बनाने में एक विशाल कदम है। उन्होंने कहा कि कई कानूनी प्रावधानों को कम करने से नवभारत की सोच को साकार करना आसान होगा और आम नागरिकों और व्यवसायियों के लिए जिंदगी सरल होगी। इस बिल से छोटे अपराधों का विवादास्पद पहलू समाप्त होगा और व्यापार का वातावरण सुधरेगा।

एलपीजी सिलेंडर का कोई संकट नहीं, कमी का बनाया जा रहा माहौल : कमलनाथ

छिंदवाड़ा। कांग्रेस के लिए एक शर्मिंदगी की स्थिति पैदा करते हुए, वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में एलपीजी की कमी के दावों को खारिज कर दिया। ऐसा करके उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी ही पार्टी के आक्रामक अभियान के विपरीत रुख अपनाया। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार केंद्र और मध्य प्रदेश सरकारों को एलपीजी सप्लाई में कथित देरी और जनता को हो रही मुश्किलों को लेकर निशाना बना रही है, वहीं कमलनाथ ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया।छिंदवाड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा, ष्ऐसी कोई कमी नहीं है। बस एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कमी है।ष उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में श्कुकिंग गैस की कोई कमी नहीं हैश और कुछ लोगों पर राजनीतिक फायदे के लिए जान–बूझकर घबराहट फैलाने का आरोप लगाया।कमलनाथ, जो मध्य

प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के प्रमुख भी हैं, ने सत्ताधारी भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी बातें इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि जनता का ध्यान शासन–प्रशासन से जुड़े मुद्दों से भटकाया जा सके। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब कई जिलों से एलपीजी डिलीवरी में देरी और वितरण केंद्रों पर लंबी कतारों की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति काफी हद तक सामान्य है और लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से गुमराह न हों।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कमलनाथ का यह बयान कांग्रेस की उस रणनीति के लिए एक झटका है।

अमित शाह के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, धुबरी में होने वाली रैली को करना पड़ा रद्द

गुवाहाटी, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण असम के धुबरी जिले के गोलकगंज में शुक्रवार को होने वाली पहली चुनावी रैली रद्द कर दी गई। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, शाह गुवाहाटी से गोलकगंज के लिए रवाना हुए थे लेकिन उनका हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका, जिसके कारण रैली रद्द कर दी गई। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग न हो पाने के कारण बाद अमित शाह ने लोगों को फोन के जरिए संबोधित किया रैली में शामिल न हो पाने के लिए माफी मांगी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार अश्विनी राय सरकार को वोट देने की अपील की, ताकि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सके और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथ मजबूत हों सकें। अमित शाह शाह ने चुनाव जीतने के बाद विजय जुलूस में शामिल होने का जनता से वादा किया। बाद में वह अपने अगले कार्यक्रम के लिए पड़ोसी ग्वालपाड़ा जिले के दुधनोई के लिए रवाना हुए। इसके बाद अमित शाह गोलपाड़ा जिले के दूधनोई में अपनी अगली जनसभा के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि गृह मंत्री दो दिवसीय असम दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने कालीआबोर में एजीपी उम्मीदवार केशव महंत के समर्थन में भी रैली की थी। शुक्रवार को उनकी तीन सभाएं प्रस्तावित थीं, जिनमें कामरूप जिले के पलाशबाड़ी में भी एक सभा शामिल थी।

असम चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हुंकार, एक–एक घुसपैठिए को बाहर निकालेगी एनडीए सरकार

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अप्रैल को असम के बारपेटा में विधानसभा चुनावों से पहले एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और कांग्रेस के बीच तीखा अंतर दिखाया। रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए सरकार ने सुरक्षा और सुशासन सुनिश्चित करते हुए भारत की संस्कृति, परंपराओं और विरासत को मजबूत करने के लिए काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार गांवों, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के विकास के लाभ

पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। "दोहरे इंजन वाली सरकार" के प्रभाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए ने एक दशक के भीतर असम को बदलने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है और इसे राज्य के लिए पुनर्जागरण का दौर बताया। असम गण परिषद (अगप) उम्मीदवार दीपक कुमार दास के समर्थन में बारपेटा में एक रैली को संबोधित करते हुए, आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने लंबे शासनकाल के दौरान राज्य और उसके लोगों की रक्षा करने में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में कांग्रेस 60 वर्षों से सत्ता में थी। लेकिन इसने घुसपैठ, हिंसा और दंगों को ही बढ़ावा दिया। इसने स्थानीय संस्कृति और विरासत को खतरे में डाल दिया। उन्होंने एआईयूडीएफ पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह घुसपैठियों को प्रोत्साहित कर रही है और उसका लक्ष्य इनके समर्थन से सत्ता पाना है। आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ मिलकर राज्य की संस्कृति और विरासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि राजग सरकार राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घुसपैठिये की पहचान करके उसे खदेड़ दिया जायेगा।

ईसीआई का आदेश, मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनावी राज्यों में मतदान के दिन सवेतन अवकाश की घोषणा की है। इस दिन कर्मचारियों के छुट्टी करने पर वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। आयोग ने नियोक्ताओं को भी सख्त हिदायत दी है। आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो मतदान करने का हकदार है, उसे मतदान के दिन सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार के सवेतन अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। जो

कोई भी नियोक्ता इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने का भागी होगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार होंगे।" ईसीआई ने आगे यह स्पष्ट किया है कि वे मतदाता (जिनमें आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी शामिल हैं) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जहां मतदान होने वाला है, वे भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के लाभ के हकदार होंगे, ताकि वे अपना मत डाल सकें। आयोग ने सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित सभी पक्षों को इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी मतदाता स्वतंत्र रूप से व सुगमतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों की घोषणा की। इसके अलावा गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा के 8 (आठ) विधानसभा

नर्मदा कुंड मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरुवार को रायपुर के नर्मदा कुंड मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने मंदिर में पूजा–अर्चना की। सीएम साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हनुमान जन्मोत्सव है। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत–बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान हनुमान जी से छत्तीसगढ़ के खुशहाली की प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ में श्री राम का अधिकतर समय वनवास के दौरान बीता था और उनके भक्त का आज जन्मोत्सव है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हमारे प्रदेश पर बनी रहे।सीएम ने आगे बताया कि नर्मदा कुंड मंदिर में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। मुझे यहां आकर काफी अच्छा लगा है। यह राम कथा 5 अप्रैल तक चलेगा। आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है और ऐसे समय पर हमारा सौभाग्य है कि नर्मदा कुंड पवित्र धाम में आने का मौका मिला। ऐसे धाम में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर पोस्ट कर कहा कि पवनपुत्र,

संकटमोचन, अतुलित बल और अटूट भक्ति के प्रतीक भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर समस्त

पीएम मोदी ने गुड फ्राइडे पर देशवासियों को दिया संदेश, करुणा और भाईचारे का किया आह्वान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे के अवसर पर देशवासियों को संदेश दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह दिन ईसा मसीह के बलिदान की याद दिलाता है और हमें उनके बताए मूल्यों पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुड फ्राइडे हमें सद्भाव, करुणा और क्षमा जैसे मूल्यों को और गहराई से अपनाने का अवसर देता है। भाईचारा और आशा हम सभी का मार्गदर्शन करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गुड फ्राइडे का यह पवित्र दिन हमें यीशु मसीह के बलिदान की याद दिलाता है और उनके प्रेम, करुणा व क्षमा के शाश्वत संदेश पर चिंतन करने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि यीशु का जीवन हमें विनम्रता, निस्वार्थता और नेकी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। साथ ही उन्होंने कामना की कि यह दिन समाज में सद्भाव और दयालुता को बढ़ाने के संकल्प को मजबूत करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संदेश में कहा कि इस पवित्र दिन पर हम ईसा मसीह के उस सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं, जो उन्होंने मानवता के लिए दिया। उन्होंने कामना की कि यह दिन हमें दयालुता अपनाने, विश्वास को मजबूत करने और समाज में सद्भाव फैलाने की प्रेरणा दे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने भी गुड फ्राइडे पर देशवासियों को संदेश देते हुए।

बेहतर पुलिसिंग व विभिन्न पर्वो को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीओ सदर सहित कई निरीक्षक व महिला थानाध्यक्ष को एडीजी लखनऊ जोन ने किया सम्मानित

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। बेहतर पुलिसिंग, शिकायतों का त्वरित निस्तारण, समाज में पुलिस के प्रति नेतृत्व व्यवहार कायम करना तथा अयोध्या में प्रमुख प्रभु को सकुशल संपन्न करने के लिए एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने अयोध्या–गोरखपुर हाईवे स्थित एक होटल में आयोजित समारोह में सम्मानित किया।जिले के कई पुलिस अधिकारियों तथा प्रभारी निरीक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने सराहनीय कार्य करने के लिए सीओ सदर अरविंद सोनकर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी पांडे ध्, महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला, राम जन्म भूमि प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या पंकज सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हुए कहा कि इन पुलिस कर्मियों ने चाहे रामनवमी हो या कोई अन्य बड़ा पर्व हो,कुंभ मेला हो उसे अपनी सूझबूझ से भीड़ को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई।कहा कि 13 जनवरी 2025 (पौष पूर्णिमा) से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 (महाशिवरात्रि) तक चले महाकुंभ मेले में अपेक्षा से कहीं अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे हालात में प्रभारी निरीक्षक अश्विनी पाण्डेय ने अपनी टीम के साथ मिलकर भीड़ को नियंत्रित करते हुए व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा।उनके नेतृत्व में श्रद्धालुओं को श्रीरामजन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और नागेश्वरनाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से दर्शन–पूजन कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।उनकी कार्यशैली और कर्तव्यनिष्ठा की अधिकारियों के साथ–साथ आम जनता ने भी सराहना की।इसके साथ ही उन्होंने 6 वर्ष से लापता एक बच्चे को सकुशल बरामद किया। इस सराहनीय कार्य के साथ कई अन्य कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया जाना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है,बल्कि पूरी पुलिस टीम के मनोबल को बढ़ाने वाला कदम भी माना जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला थाना अध्यक्ष आशा शुक्ला तथा उनकी पुलिस टीम द्वारा महाकुंभ मेले रामनवमी तथा अयोध्या मे आयोजित होने वाले अन्य प्रमुख पर्वों में सराहनीय भूमिका निभाने का कार्य किया है इसके साथ ही साथ उनके तथा उनकी टीम द्वारा महिला थाना परिसर में आने वाली महिलाओ की समस्याओं का त्वरित निराकरण भी कर रही है जिसको लेकर उनकी कितनी तारीख की जाए कम है इसीलिए उनको भी यह सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है।

संपादकीय

डेमोग्रैफिक डिविडेंड गंवा देने का खतरा

जो देश अपनी युवा श्रमशक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, उनके संबंध में आम समझ है कि वे धनी होने से पहले बूढ़ा हो जाते हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर डेमोग्रैफिक डिविडेंड गंवा देने का खतरा मंडरा रहा है। युवा आबादी के संभावित लाभ को भारत गंवाने जा रहा है– यह निष्कर्ष है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के श्भारत में कामकाज की स्थिति–2026च रिपोर्ट का। इसके मुताबिक 2030 में युवा आबादी (15– 29 वर्ष) अपनी चरम संख्या पर पहुंच जाएगी। उसके बाद इसमें गिरावट आने लगेगी। फिलहाल 36.7 करोड़ युवा इस उम्र वर्ग में हैं, जो कुल कामकाजी उम्र की आबादी का एक तिहाई हिस्सा है। मगर उनमें से 26.3 करोड़ ना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ना रोजगार में हैं। अतरू उनके श्रमशक्ति का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, श्आने वाले दशक में युवा पीढ़ी के लिए रोजगार सृजन की गति यह तय करेगी कि डेमोग्रैफिक डिविडेंड आर्थिक लाभ में तब्दील होता है या नहीं।च मगर रोजगार की सूरत यह है कि सिर्फ सात प्रतिशत पुरुष स्नातकों को डिग्री लेने के बाद पहले साल में नियमित वेतन वाली नौकरी मिल पाती है। ह्वाइट कॉलर जॉब्स की बात करें, तो यह संख्या महज 3.7 फीसदी है। तो रिपोर्ट में कहा गया है– श्ये संख्याएं चिंताजनक सूरत की झलक हैं। सुरक्षित ह्वाइट कॉलर जॉब ढूंढना अत्यधिक दुर्लभ घटना बनी हुई है।च वैसे चिंताजनक अनेक अन्य आंकड़े भी रिपोर्ट में हैं। उनमें एक बेरोजगार स्नातकों की विस्फोटक ढंग से बढ़ती गई संख्या है। 2004 में 30 लाख स्नातक बेरोजगार थे। यह संख्या 2011 में 40 लाख पहुंच गई। 2011–17 में इसमें बेहद तेज रफ्तार से बढ़ोतरी हुई। 2023 तक ये तदाद एक करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। इन स्थितियों के साथ कोई देश आर्थिक महाशक्ति बनने की कैसी उम्मीद जोड़ सकता है? जो देश अपनी युवा श्रमशक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, उनके संबंध में आम आर्थिक समझ है कि वे धनी होने से पहले बूढ़ा हो जाते हैं। विश्व बैंक की श्रेणी के मुताबिक भारत लगभग तीन हजार डॉलर सालाना प्रति व्यक्ति आय के साथ अभी भी निम्न– मध्यम आय वर्ग वाला देश है। यानी धनी होने के पहले उसे उच्च मध्य वर्ग की श्रेणी (4,500 से 14000 डॉलर) पार करनी है। जबकि युवा आबादी की संख्या में वृद्धि के अब सिर्फ चार साल बाकी हैं।

माओवाद का खात्मा और साय सरकार की पुनर्वास नीति

उमेश

कभी देश के एक तिहाई हिस्से पर अपनी समानांतर सरकार चलाने वाली माओवादी विचारधारा का क्या आज अंत हो जाएगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्रीय सरकार ने आज ही के दिन को माओवादी आतंकवाद का आखिरी दिन घोषित कर रखा है। ठीक एक हफ्ते पहले यानी 25 मार्च को बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में शीर्ष माओवादी नेता पापा राव के नेतृत्व में 18 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, तब कहा गया कि राव आखिरी महत्वपूर्ण नक्सली कमांडर हैं और उन्होंने भी हथियार सौंप दिए हैं। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में माओवाद पर लगाम का वादा किया था। तब झीरम घाटी कांड की याद ताजा थी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का तकरीबन समूचे शीर्ष नेतृत्व को माओवादियों ने घेरकर मार डाला था। वैसे खुद नक्सली भी मानते रहे हैं कि उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी सरकारों में खास अंतर नहीं रहा। अलबत्ता कांग्रेस सरकार माओवादी हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाने से बचती रही हैं, जिस तरह बीजेपी की अगुआई वाली सरकारें उठाती रही हैं। बस्तर में छह अप्रैल 2010 को बारूदी सुरंगों के जरिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों को उड़ाने के बाद नक्सलियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी गुस्सा था। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने माओवादियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का मन बना लिया था, लेकिन सिविल सोसायटी के दबाव में यह विचार उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने माओवादियों को कोई रियायत नहीं दी। 2019 में गृहमंत्रालय की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने खुलेआम नक्सलियों को चेतावनी देनी शुरू कर दी कि या तो वे हथियार डालें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही उन्होंने 31 मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा से देश को मुक्त करने का ऐलान कर दिया। जिस तरह शीर्ष नक्सली कमांडर या तो मारे गए हैं या फिर उन्होंने हथियार डाले हैं, उससे लगता है कि बीजेपी सरकार का अपना वादा पूरा करने जा रही है। माओवादी विचारधारा के प्रभाव में घर–परिवार, सुख–चौन छोड़कर जंगलों की खाक छानने और सत्ता से जूझने वाले माओवादी युवाओं को मुख्यधारा में लाने में सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलियों का दबाव ही काम नहीं आया, बल्कि इसमें राज्यों की पुनर्वास योजनाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ ने 2025–26 की अपनी पुनर्वास नीति में हिंसा छोड़ने वाले नक्सलियों को मुख्यध ारा से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें उसका श्पूना मारगेमश अभियान प्रमुख रहा। इन शब्दों का अर्थ है श्नया रास्ता'। इसके तहत दंडकारण्य क्षेत्र के सैकड़ों माओवादी कैडरों को मुख्यधारा में वापस लाने की सफल कोशिश हुई। इसके तहत नक्सलियों की वापसी के बाद उन्हें नई जिंदगी शुरू करने के लिए तत्काल डेढ़ लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता दी गई, साथ ही उन्हें तीन साल के लिए मासिक वजीफा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना शुरू हुआ। मकसद यह रहा कि हथियार छोड़ने के बाद मुख्यधारा में लौटे माओवादी आत्मनिर्भर जिंदगी बिता सकें। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने हथियार सौंपने वाले माओवादियों को अलग से प्रोत्साहन राशि देने की भी व्यवस्था की। इससे राज्य में माओवादियों के समर्पण में तेजी आई। हथियार छोड़ने वाले माओवादियों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया गया, इसके साथ ही उन्हें सुरक्षित आवास भी मुहैया कराए गए। इसके साथ ही उन्हें वापसी के बाद भयमुक्त जीवन गुजारने के लिए परिवार की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई। इसी तरह झारकंड सरकार ने भी माओवादियों को समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए श्आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीतिश बनाई। जिसके तहत समर्पण के बाद माओवादियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। उनके कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन्हें रोजगार के साथ ही आवास की व्यवस्था की जाती है। साथ ही उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। झारखंड की इस नीति का उद्देश्य समर्पित नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत हथियार जमा करने पर पूर्व नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि, उन्हें तत्काल पुनर्वास अनुदान और घरेलू सामान के लिए नकद सहायता दी जाती है। साथ ही उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे भविष्य में अपना रोजगार कर सकें। इसके साथ ही उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा व छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जाती है। उन्हें आवास के लिए भूमि या प्रध ाानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिए जाते हैं। इसी तरह मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों को खेती के लिए प्राथमिकता के आधार पर सोलर पंप और बिजली कनेक्शन भी देने का इंतजाम है। पूर्व नक्सलियों पर चल रहे छोटे मामलों को झारखंड सरकार जहां वापस ले रही है, वहीं गंभीर मामलों में कानूनी सहायता मुहैया करा रही है। कुछ ऐसे ही इंतजाम पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में किए गए हैं। कभी माओवादियों के डर से बस्तर में सड़कें तक बनाना संभव नहीं था, बिजली पहुंचाना भी कठिन था। झारखंड के भी दूरदराज के इलाके में ऐसा ही हाल था। लेकिन केंद्र सरकार की शह पर राज्य सरकार ने नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्र में भी सड़क, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण कराने में तेजी आई। बस्तर के कुछ इलाके में रेलवे लाइन भी पहुंच गई है। नक्सली इलाके में सड़कें भी बेहतर हो गई हैं। इन कदमों से माओवादी प्रभाव में रहने वाले इलाकों में भरोसा बहाली में मदद मिली। सरकारी योजनाओं के साथ ही सरकार के प्रति भी स्थानीय लोगों का रवैया बदला। कभी पशुपति से तिरुपति यानी नेपाल से आंध्र तक का जंगली इलाका लाल गलियारे के रूप में विख्यात था। यहां सुरक्षा बलों के लिए भी घुसना आसान नहीं था। इसमें देश के तकरीबन एक तिहाई जिले आते थे। इन जिलों में माओवादी वैचारिकी के असर वाले हथियारबंद दस्तों की सत्ता चलती थी। माओवादी स्कूलों, रेलवे लाइनों, पुलिस थानों, डाकघरों को निशाना बनाते थे। साथ ही वे इलाके की जनता को यह समझाने में कामयाब रहे थे कि मौजूदा व्यवस्था और तंत्र सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण ही कर रहा है। चूंकि विकास की धारा इन इलाकों में माओवादी हथियारबंद दस्तों के अवरोध के चलते बह नहीं पा रही थी, इसलिए अविश्वास का माहौल बढ़ता रहा। लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही एक तरफ माओवादियों को उन्हीं की तर्ज में गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ उनके पुनर्वास के साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धारा को भी बहाने की कोशिश तेज की। माओवादी कहते रहे हैं कि सत्ता की राह बंदूक की गोली से निकलती है, बारूद से निकलती है, मोदी सरकार ने कुछ उसी अंदाज में माओवादी सत्ता की राह को बंदूक और बारूद से रोका, लेकिन दूसरी तरफ पुनर्वास अभियान भी जारी रखा। इसमें राज्यों की भूमिका खास रही। चूंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, इसलिए दोनों राज्यों ने इसमें बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। जिसका नतीजा सामने है। कभी पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हिंसक और माओवादी विचारध ाारा का असर देश के एक तिहाई हिस्से पर रहा। लेकिन अब यह विचारध ाारा और उसके हथियारबंद अनुयायी निस्तेज नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि वामपंथ की तरह माओवादी विचारधारा भी भारत में कुंद हो गई। नक्सली हिंसा पर लगाम इस लगाम का ही प्रतीक है।

भाजपा को मिली कामयाबी

हरिशंकर व्यास

बिहार में नीतीश कुमार का शासन नरेंद्र मोदी के लिए दुखती रग की तरह था। आखिर नीतीश एनडीए के इकलौते नेता थे, जिन्होंने 2013 में मोदी को एनडीए की चुनाव समिति का प्रमुख और बाद में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने का विरोध करते हुए एनडीए छोड़ा था। इसके बाद वे अकेले चुनाव लड़े और मोदी ने रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से तालमेल करके चुनाव लड़ा। उस चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उसने अकेले 243 सीटें मिलीं और एनडीए ने 32 सीटें जीतीं। नीतीश कुमार की पार्टी दो सीटों पर सिमट गई। तो मोदी को लगा कि उन्होंने नीतीश को हैसियत दिखा दी। नीतीश को भी हकीकत का अहसास हुआ तो उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में अपने धुर विरोधी लालू प्रसाद और कांग्रेस से तालमेल कर लिया। नवंबर 2015 से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जुलाई के महीने में नरेंद्र मोदी बतौर प्रध ाानमंत्री बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सभा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश के डीएनए में गड़बड़ी है। इसके चार महीने के बाद चुनाव में नीतीश और लालू की जोड़ी ने भाजपा और उसके सहयोगियों को बुरी तरह से हराया। मोदी प्रधानमंत्री थे

और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा गठबंधन को बिहार की 243 में से सिर्फ 59 सीटें मिलीं। इस हार ने मोदी और शाह को मजबूर किया कि वे नीतीश के साथ फिर से तालमेल करें। झक्ख मार कर उन्हें नीतीश को एनडीए में लाना पड़ा और मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मोदी और शाह की नीतीश के प्रति कैसी कुंठा या खुन्नस थी यह 2020 के चुनाव में फिर दिखा। डीएनए पर सवाल उठाने के बाद वाले चुनाव में भाजपा ने नीतीश को निपटाने का पूरा प्लान बनाया और चिराग पासवान को गठबंधन से अलग चुनाव लड़वाया। चिराग को सारे संसाधन भाजपा ने दिए यहां तक कि ज्यादातर उम्मीदवार भी भाजपा ने ही दिए, जो बाद में फिर भाजपा में लौट आए। चिराग को चुनाव नहीं जीतना था, बल्कि नीतीश को हरवाना था। इसमें काफी हद तक कामयाबी मिली। लेकिन नतीजे भाजपा के मनमाफिक नहीं आए। नीतीश तो 43 ही सीट जीत पाए लेकिन दूसरे ओर राजद 75 सीट जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। महागठबंधन को 110 सीटें मिल गईं। सो, फिर मजबूरी हो गई कि नीतीश को सीएम बनाया जाए। हालांकि इसके बावजूद भाजपा को हैसियत दिखाने के लिए नीतीश एक बार फिर राजद के साथ जाकर सरकार बनाई। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया और श्इंडियाच्च ब्लॉक का गठन भी कराया। फिर मजबूरी में भाजपा को नीतीश कुमार की वापसी करानी पड़ी और बराबर सीटें देकर समझौता करना पड़ा। भाजपा को नीतीश का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उनकी वजह से बिहार में एनडीए को लोकसभा में 30 सीटें मिलीं और विधानसभा में 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन 2013 से ही नीतीश को खत्म करने की ग्रंथि पाले भाजपा नेताओं ने शुक्रगुजार होने की बजाय पहला मौका मिलते ही उनको निपटा दिया। इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी 85 सीटों पर जीती लेकिन विधानसभा का गणित ऐसा बन गया कि नीतीश के लिए दूसरे पाले में जाकर सरकार बनाना मुश्किल हो गया। दूसरे, भारत की राजनीति के सबसे अधिक कैलकुलेटिंग माइंड वाले नेता नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था बिगड़ गई। वे भूलने की बीमारी से ग्रस्त हो गए। तभी भाजपा ने उन पर अंतिम वार किया और निपटा दिया। नीतीश को और उनकी राजनीति को समाप्त करने का प्रयास पिछले 13 साल से किया जा रहा था। कामयाबी तब मिली, जब उनकी मानसिक दशा बिगड़ी। भाजपा ने उनके लाचार होने का फायदा उठा कर बेहद अपमानजनक तरीके से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का बंदोबस्त किया और अपना मुख्यमंत्री बनाने की व्यवस्था की।

अर्थव्यवस्था दुरुस्त है लेकिन प्रबंधन दोषपूर्ण!

अरविन्द

सर्राफा बाजार सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी और काला सफेद का खेल खेलने का मैदान बन गया है। चांदी की सट्टेबाजी की चर्चा ज्यादा रही लेकिन सरकार ने वायदा बाजार पर भी किसी तरह की सख्ती करके सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया है। दुर्भाग्य यह है कि सोना चांदी में निवेश का रोग इधर ध ीरे–धीरे वैश्विक बन गया है। आज यह गिरावट भारत में ही नहीं वैश्विक है। देर से ही सही लेकिन जब प्रध ाानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान इजरायल–अमेरिका युद्ध को लेकर संसद में और बाहर भी जब कभी भी कुछ कहा है तो वे स्थिति को गंभीर बताते हैं। लेकिन सोमवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनके ऊपर अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का असली जिम्मा है, ने संसद में बयान दिया तो उनके कहने का मतलब ठीक वैसा नहीं था जैसा प्रधानमंत्री की चिंता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत बताने के साथ ही रुपये की गिरावट को अन्य एशियाई देशों की मुद्राओं की तुलना में कम ही बताया। जिस दिन रुपया डालर के मुकाबले 95 के स्तर को छूकर वापस आया उस दिन ही हमारी वित्त मंत्री 4.1 फीसदी की गिरावट को कुछ ऐसा बता रही थीं कि पश्चिम एशिया संकट कोई चीज नहीं है। उन्होंने उसी दिन शेयर बाजार और सर्राफा बाजार की गिरावट का जिक्र करना भी जरूरी नहीं माना और सरकार द्वारा इस बीच उठाए कदमों की चर्चा भी नहीं की। हम जानते हैं कि सरकार ने पहले तो पेट्रोलियम वितरण में सबसे बड़ी निजी कंपनी को दाम बढ़ाने की छूट दी और फिर कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाए। इससे भी आगे बढ़ाकर उसने विभिन्न करों में कटौती वापस लेकर तेल कंपनियों को लगभग दस रुपये लीटर का अतिरिक्त लाभ लेने की इजाजत दी। पहले यह धन सरकारी खजाने में आता था। बीते वर्षों में इससे सरकार को चालीस लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह अभी घटा है, खत्म नहीं हुआ है। अब वित्त मंत्री को इन पक्षों की चर्चा करने में क्या दिक्कत थी इसे समझना तो मुश्किल है लेकिन यह समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर पांच राज्यों में विध ाान सभा चुनाव न होते तो अब तक तेल और गैस की कीमतों में आग लग चुकी होती। और जो प्रधानमंत्री आजकल अर्थव्यवस्था की या मुल्क की हालत की चर्चा करते समय गंभीरता की चादर ओढ़े रहते हैं वही परेशानियों का शोर मचाते रहते हैं। आज वे और उनके समर्थक(जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं) लगातार यही सूचना दे रहे हैं कि कहीं कमी नहीं है, सिर्फ विपक्ष अफवाह फैला रहा है। जाने कितने जहाज तेल और गैस लेकर होर्मुज से आगे बढ़ चुके हैं। जबकि ऐसे जहाजों की संख्या पहले की तुलना में काफी घट गई है और ईरान ने भी बहुत मान मनौव्वल के बाद कुछ जहाजों को आने की इजाजत दी। उन पर बीमा का खर्च समेत बाकी क्या बोझ बढ़ा है उसका हिसाब अलग है। इस बीच हमारी सरकार ने रूस से तेल लेने में जो व्यवहार दिखाया है (और उसमें अमेरिकी दबाव बहुत साफ दिखता है) उससे नाराज रूस अब तेल देना ही बंद कर रहा है। इसलिए सिर्फ तेल वाले पक्ष की ही चर्चा हो तो उस पर वित्तमंत्री को काफी कुछ कहना था।वे बोलें न बोलें सामान्य समझ और बाहर दिख रहे दृश्य यह बताते हैं कि सचमुच के हाहाकार की स्थिति है। और अगर युद्ध अब जरा भी लंबा खींचा तो अर्थव्यवस्था के पूरे स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेगा ही हमारी रसोई और पारिवारिक बजट को चौपट कर देगा। गैस की कमी ने होटलों–रेस्तरां में मेन्यू बदला है तो कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। कुछ उद्योग तो सीध ो प्रभावित हो रहे हैं तो बाकी पर भी असर आएगा ही। निश्चित रूप से सरकार की एजेंसियां अपने काम में कुछ ज्यादा तत्पर हुई हैं लेकिन यह तत्परता देर से शुरू हुई है। जब प्रध ाानमंत्री युद्ध शुरू होने के दो दिन पहले इजरायल में घूमने फिरने जाते हैं तो बाकी लोग कैसे आपात स्थिति की तैयारी कर सकते हैं। जब युद्ध की मार पड़ती है तो इजरायल अपनी स्थिति देखेगा और अमेरिका खाड़ी के अपने चेले चपाटियों की रक्षा करेगा या आपकी चिंता करेगा। और जब ईरान के ऊपर गलत हमले और उसके शासन प्रमुख की हत्या पर आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकलते तो वह युद्ध लड़ते हुए आपको कैसे कंधे पर बैठाए घूमेगा। फिर तो आपको अपनी तैयारी और प्रबंधन से ही काम करना होता जो आपने दिखाई नहीं।आज चुनावी चिंता से जो चौकसी दिखती है वही कुछ समय पहले से शुरू रहती तो कई मामलों में हम बेहतर स्थिति में होते क्योंकि युद्ध से हमारा नाता बहुत दूर–दूर का ही है और हमने बाद में बेमतलब टांग अड़ाकर अपना नुकसान कराने वाली स्थिति नहीं बनाई है। लेकिन इस दौरान शेयर बाजार, करेंसी बाजार और सर्राफा बाजार में जिस तरह की घबराहट और बेचौनी दिख रही है उसका काफी कुछ तो हमारा खुद का बनाया हुआ है। जाने कब से जानकार कह रहे हैं कि हमारा शेयर बाजार ओवर रेटेड है अर्थात जितना अच्छा हाल कम्पनियों का नहीं है उससे कहीं ज्यादा बढ़िया हाल उनके शेयरों का है। जाहिर है इस बनावटी खेल में सरकार और उसकी कर्ता–ध र्ता संस्थाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई है, साझा कोषों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की) ने सरकार के निर्देश पर ही बाजार को ऊपर ही ऊपर बनाए रखा है–कुछ खास कंपनियों और समूहों के शेयरों पर खास कृपया बरसती रही है। अब युद्ध का असर तो दुनिया भर के बाजारों पर हुआ है। कायदे से उन बाजारों पर ज्यादा असर आना चाहिए था जिनके देश युद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उलझे हैं। लेकिन बिना युद्ध में लगे हमारे बाजार गिरावट में सबको मात देने के खेल में जुटे हैं।सर्राफा बाजार सिर्फ और सिर्फ मुनाफाखोरी और काला सफेद का खेल खेलने का मैदान बन गया है। चांदी की सट्टेबाजी की चर्चा ज्यादा रही लेकिन सरकार ने वायदा बाजार पर भी किसी तरह की सख्ती करके सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया है। दुर्भाग्य यह है कि सोना चांदी में निवेश का रोग इधर धीरे–धीरे वैश्विक बन गया है। आज यह गिरावट भारत में ही नहीं वैश्विक है लेकिन भारत जैसी स्थिति कहीं और नहीं है।

पता नहीं आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा

अजीत द्विवेदी

दस साल हो गए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत अपनी ऊर्जा जरुरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करेगा। प्रध ाानमंत्री मोदी ने सात फरवरी 2016 को ओडिशा के पारादीप में भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी की एक रिफाइनरी का उद्घाटन करते हुए यह बात कही थी। उन्होंने उस समय एक लक्ष्य भी तय किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक भारत अपनी ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने के लिए विदेशी निर्भरता को 10 फीसदी तक कम करेगा। उस समय भारत 80 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता था। आज 10 साल बाद भारत का कच्चे तेल का आयात 85 फीसदी से ज्यादा हो गया है। यानी जहां दस फीसदी आयात कम होना था वहां पांच फीसदी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने आयात पर निर्भरता 10 फीसदी घटाने के लक्ष्य के साथ साथ यह भी कहा था कि ऊर्जा जरुरतों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने चार क्षेत्र बताए थे, जहां काम किया जाना था। इसमें इथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाना और तेल, गैस आदि की खोज को प्रोत्साहित करना शामिल था। सोचें, 10 साल पहले ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रध ाानमंत्री के मुंह से सुनना कितना अच्छा लगा होगा! उसमें भी तात्कालिक लक्ष्य आयात में 10 फीसदी की कमी का रखा गया था। एक ब्लूप्रिंट भी पेश किया गया। लेकिन 10 साल के बाद देश कहां पहुंचा? आज स्थिति यह है कि भारत अपनी ऊर्जा जरुरतों के लिए दूसरे देशों पर पहले से ज्यादा निर्भर हो गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल के मामले में भारत की निर्भरता बढ़ी है। हकीकत यह है कि जिस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का संकल्प किया गया था उनके लिए भी भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है पर उसकी लिए बैटरी और दूसरी कई तकनीकी चीजें चीन से आएंगी। इसी तरह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का मामला है तो उसके लिए भी सोलर प्लेट्स में लगने वाले कल पुर्जे और दूसरे उपकरण चीन से आएंगे। सोचें, हम तेल के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के मामले में भी दूसरे देशों पर निर्भर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल में इन क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन थोड़े से काम होने से तो देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन जाएगा? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल आयात में 10 फीसदी की कमी की जाएगी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में कोई योजना होगी, लंबे समय की कोई प्लानिंग होगी! फिर किसने उनको उस योजना पर काम नहीं करने दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आत्मनिर्भरता की योजना के नाम पर थोड़ा सा उत्पादन बढ़ाने की योजना हो? जब इतनी बड़ी घोषणा की जाती है तो उसे पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा प्रयास करना होता है। उस प्रयास में स्पष्ट कमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि समय समय पर इस तरह की बातें करके प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा तो दिया कि वे देश की समस्या को समझ रहे हैं और उसका समाधान करना चाहते हैं। लेकिन समाधान की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। उन्होंने 2016 के बाद तेल आयात कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात अनेक बार कही। लेकिन सवाल है कि क्या वे देख नहीं रहे थे कि उनकी बातों या दावों में और देश की वास्तविकता में कितना अंतर है? आज जब संकट देश के सामने आया तो सबका ध्यान इस वास्तविकता की ओर गया है। ईरान में जंग शुरू हुए 12 दिन हुए हैं और भारत में हाहाकार मचा है। भारत सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एस्मा लागू करना पड़ा है। हालांकि रसोई गैस का मामला कालाबाजारी का भी है। लेकिन यह भी सही है कि किल्लत बढ़ रही है क्योंकि भारत अपनी एलपीजी की जरुरतों का 80 फीसदी से ज्यादा खाड़ी के देशों से आयात करता है और उसके भंडारण की भी वैसी व्यवस्था देश में नहीं है, जैसी कच्चे तेल के लिए है। इसलिए संकट तो है। तभी देश भर में होटल और रेस्तरां बंद हो रहे हैं और सरकार को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति के नियम बनाने पड़े हैं। सरकार ने घरेलू आवंटन को सौ फीसदी रखने को कहा है लेकिन उद्योगों और व्यावसायिक संस्थाओं के आवंटन में 20 से 30 फीसदी की कटौती हुई है। एलपीजी के अलावा तेल का संकट भी है तभी विमानन कंपनियों ने किराया बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कम होने से उर्वरक से लेकर प्लास्टिक उद्योग तक करीब 75 उद्योग हैं, जहां असर हुआ है। उर्वरक के उत्पादन पर असर होगा तो अंततरू उससे खाद्यान्न सुरक्षा भी प्रभावित होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ने की घोषणा के 10 साल हुए हैं तो श्आत्मनिर्भर भारत अभियान्च के भी छह साल होने जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के एक राहत पैकेज की घोषणा भी हुई थी। हालांकि वह पूरी तरह से क्रेडिट गारंटी की योजना थी। किसी को मदद के तौर पर इसमें से एक रुपया नहीं मिला, बल्कि सबको कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी।

जौनपुर में करंट से तीन की मौत – मुख्य अभियंता को जांच के आदेश, 7 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। नगर कोतवाली थाना अंतर्गत मछलीशहर पड़ाव के पास बिजली के खंभे में विद्युत करंट लगने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने गंभीर रुख अपनाते हुए शनिवार को जांच के आदेश दिए हैं। वाराणसी क्षेत्र के मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई है और उन्हें 7 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। मामले में मियापुर लाइन बाजार निवासी साक्षी मिश्रा ने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह एवं हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता (जौनपुर शहरी), लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, मुख्य राजस्व अधिकारी तथा जल निगम के संबंधित अधिकारियों समेत अन्य कर्मचारियों पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार, 25 अगस्त 2025 को मछलीशहर पड़ाव के पास सड़क पर एक गड्ढा था, जहां बिजली के खंभे से लटक रहा जर्जर तार टूटकर गिरा हुआ था। इससे गड्ढे में करंट प्रवाहित हो रहा था। इसी दौरान साक्षी मिश्रा की बहन प्राची मिश्रा वहां से गुजरते समय गड्ढे में गिर गईं और करंट की चपेट में आ गईं। बताया गया कि टूटी नाली के ढक्कन के कारण हादसा और गंभीर हो गया। घटना के लगभग 28 घंटे बाद उनका शव खुले नाले से बरामद हुआ। उन्हें बचाने के प्रयास में दो अन्य लोग भी करंट की चपेट में आ गए और बहकर उनकी भी मौत हो गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि संबंधित विभागों की घोर लापरवाही और उपेक्षा के कारण यह हादसा हुआ। प्रार्थी ने पहले कोतवाली थाना और पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अब न्यायालय के आदेश के बाद मामले की जांच तेज होने की उम्मीद है।

हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है - गिरीश चंद्र यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में नए शैक्षिक सत्र 2026–27 के तहत 'स्कूल चलो अभियान' का भव्य शुभारंभ शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा डायट परिसर में आयोजित समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव रहे, जबकि जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने अध्यक्षता की और मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन के साथ अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, वहीं मुख्यमंत्री द्वारा वाराणसी से अभियान के शुभारंभ का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर बच्चों का नामांकन किया गया तथा उन्हें निशुल्क पाठ्य–पुस्तकें, यूनिफॉर्म और बैग वितरित किए गए। इसके बाद 'स्कूल चलो रैली' निकाली गई, जिसे मंत्री व सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरते हुए पुनः डायट परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में छात्र–छात्राएं और शिक्षक "सब पढ़ें, सब बढ़ें", "आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे" जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक करते नजर आए। बैंड–बाजे और सजे रथों के साथ निकली इस रैली ने पूरे शहर में शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश फैलाया। मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि "हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।"उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें और उनकी पढ़ाई में रुचि लें। उन्होंने आगे कहा कि परिषदीय विद्यालयों में अब बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैंकृजैसे निशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म, मिड–डे मील और डिजिटल शिक्षा की पहलकृजिससे गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके।"शिक्षा ही वह माध्यम है जो बच्चों के भविष्य को संवारती है और समाज को मजबूत बनाती है," उन्होंने जोर देकर कहा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए घर–घर जाकर नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अभियान का पहला चरण 15 अप्रैल तक तथा दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि ड्रॉपआउट और दिव्यांग बच्चों के नामांकन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक–शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

अधूरे परीक्षा परिणाम पर छात्रों का हंगामा, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय घेरा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शनिवार को टीडी कॉलेज के बीएससी तृतीय वर्ष के छात्रों ने अधूरे परीक्षा परिणाम के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। करीब डेढ़ सौ छात्रों ने कुलपति कार्यालय के सामने धरना देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश में कार्यालय का दरवाजा तोड़ने का प्रयास भी किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र बीएससी तृतीय वर्ष के पांचवें सेमेस्टर के थे। उनका आरोप था कि हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम में गंभीर त्रुटियां हैं, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों के अनुसार, सत्र 2025–26 के परिणाम में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित जैसे विषयों में लगभग 350 छात्रों के परिणाम अधूरे या गलत घोषित किए गए हैं। छात्रों ने बताया कि इस समस्या को लेकर वे पहले भी कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी उपेक्षा से नाराज होकर उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कुलपति कार्यालय के दरवाजे को पीटते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया। उपकुलसचिव अजीत प्रताप सिंह, प्रो. अजय प्रताप सिंह, डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर और डॉ. प्रवीण सिंह समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और कुलपति व परीक्षा नियंत्रक से तत्काल मुलाकात की मांग करते रहे। काफी देर तक चले गतिरोध के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद देर शाम छात्र शांत हुए और अपना धरना समाप्त कर दिया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनके परिणामों में सुधार नहीं किया गया, तो वे फिर से उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

यूपी के मौसम में बदलाव के संकेत, कई जिलों में बारिश संग गिर सकते हैं ओले, तपिश से मिलेगी राहत

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। कभी तेज धूप तो कई जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश और ओले भी गिर रहे हैं। बृहस्पतिवार को दिन में तेज धूप रही पर रात में कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से सहारनपुर, शामली, मेरठ, नोएडा समेत पश्चिम के 18 जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है।

शुक्रवार और शनिवार के बीच बारिश के साथ ही इन जिलों में वज्रपात और ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। करीब 11 जिलों में ओले गिर सकते हैं। इधर बृहस्पतिवार को धूप की तपिश और भीषण गर्मी ने लोगों को असहज किया। बांदा में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। जबकि प्रयागराज में 40 डिग्री, वाराणसी व हमीरपुर में 39.5 डिग्री और कानपुर में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार से विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी यूपी से बारिश का दौर शुरू होकर शनिवार को पूर्वी यूपी में पहुंचेगा। इस दौरान कई हिस्सों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और ओलेगिरने की भी संभावना जताई गई है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, महोबा, झांसी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर ललितपुर व आसपास के इलाकों में।

टोल बढ़ा, अब रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ेगा

लखनऊ, (संवाददाता)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से लखनऊ–आगरा एक्सप्रेसवे सहित चारों एक्सप्रेसवे पर टोल की नई दरें लागू की गई हैं। इसे देखते हुए रोडवेज बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी है। रोडवेज प्रशासन ने सभी प्रधान प्रबंधक, आईटी को पत्र लिखकर बसों के किराये में संशोधन के लिए पत्र लिखा है। रोडवेज लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि टोल प्लाजा पर पहली अप्रैल से नई दरें लागू कर दी गई हैं। ऐसे में बसों का खर्च बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि अहमदपुर टोल प्लाजा पर सिंगल एक्सेल व मल्टी एक्सेल वाहनों के लिए क्रमशरू 385 और 420 रुपये टोल है। ऐसे ही बाराबंकी–जरवल रोड के शहावपुर टोल पर 140, 150 रुपये, लखनऊ–सुल्तानपुर के बारा टोल प्लाजा पर 375, 405 रुपये, रायबरेली–कानपुर के ऐहार टोल प्लाजा पर 215, 235 रुपये, लखनऊ–रायबरेली के दखिना शेखपुर टोल 410, 445 रुपये, लखनऊ–सीतापुर रूट के इटौंजा टोल पर 195, 310 रुपये, रायबरेली–प्रतापगढ़ के नुरुद्दीन टोल पर 290, 320 रुपये, रायबरेली–प्रयागराज के इटौरा टोल पर 290, 315 रुपये, लखनऊ–कानपुर के नवाबगंज टोल प्लाजा पर 330, 360 रुपये शुल्क कर दिया गया है। ऐसे में इन टोल से गुजरने वाली बसों के किराये में संशोधन के लिए कहा गया है।

मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह के तहत सूचना विभाग में कार्यशाला आयोजित

लखनऊ, (संवाददाता)। भारत सरकार द्वारा विकसित आईगोट (प्ळव्ज्) पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों के माध्यम से विभागीय कार्मिकों की कार्यात्मक क्षमता और तकनीकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में 02 अप्रैल से 08 अप्रैल 2026 तक मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना विभाग के विभागीय ऑडिटोरियम में मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह के अंतर्गत एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर आईगोट पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों से संबंधित तकनीकी जानकारी विशेषज्ञों से प्राप्त की। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बताया गया कि आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से कम से कम 4 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

संक्षिप्त खबरें

ऐशबाग स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक 15 जुलाई तक होगा पूर्ण

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि लखनऊ के ऐशबाग स्थित संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण आगामी 15 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह स्मारक एक प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसे भव्य स्वरूप देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सदस्य विधान परिषद लाल जी प्रसाद निर्मल तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ निर्माणाधीन स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को सभी कार्य गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि स्मारक का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है, जबकि द्वितीय चरण के अंतर्गत 500 व्यक्तियों की क्षमता वाले प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इस भवन में डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन संघर्षों पर आधारित संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, जिससे देशभर के लोग उनके जीवन और योगदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही यहां एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जा रहा है, जहां युवा पीढ़ी बाबा साहेब के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगी।पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 जुलाई 2026 की निर्धारित समय–सीमा को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की जाए तथा किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।

छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को राहत, समाज कल्याण विभाग फिर खोलेगा पोर्टल

लखनऊ, (संवाददाता)। किसी भी कारणवश छात्रवृत्ति से वंचित रह गए छात्रों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। समाज कल्याण विभाग शैक्षिक सत्र 2025–26 के अंतर्गत संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के छूटे हुए छात्रों के लिए एक बार फिर पोर्टल खोलने जा रहा है, ताकि सभी पात्र छात्र–छात्राएं दोबारा आवेदन कर छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। इस सुविधा का लाभ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को मिलेगा। विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य छात्र केवल तकनीकी या अन्य कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।समाज कल्याण विभाग के अनुसार, पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के तहत पोर्टल खोला गया था, जिसके माध्यम से 53,041 छात्रों को कुल 81.12 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 25,395 छात्रों को 30.65 करोड़ रुपये तथा सामान्य वर्ग के 27,646 छात्रों को 50.47 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी।समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर समुदाय के छात्रों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

राज्यपाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की समीक्षा की

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को जन भवन स्थित गांधी सभागार में लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय एवं वित्त पोषित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय से संबद्ध 17 शासकीय तथा 33 वित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित रहे।बैठक के दौरान सभी महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने अपने–अपने संस्थानों की विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें महाविद्यालयों की प्रगति रिपोर्ट, फैकल्टी की स्थिति, विभागों की कार्यप्रणाली, शोध एवं प्रकाशन, एमओयू, खेल गतिविधियां, सामाजिक सहभागिता, पौधारोपण अभियान, नैक एवं एनआईआरएफ रैंकिंग, छात्र–छात्राओं के नामांकन, प्लेसमेंट, रोजगार मेले, पेटेंट, शोध पत्र, सेमिनार, पुस्तकालय सुविधाएं, निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रयोगशालाओं एवं कंप्यूटर कक्षों की स्थिति, छात्रवृत्ति वितरण तथा शैक्षणिक भ्रमण से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई।राज्यपाल ने महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अनुपात, खेल गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी तथा पौधारोपण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि महाविद्यालयों में आयोजित सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ्स को जियो–टैगिंग के साथ सुरक्षित रखा जाए।उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रेरित करने तथा अपनी सक्रियता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक के पिता राधेश्याम पाठक के निधन पर भाजपा नेताओं ने जताया शोक

लखनऊ, (संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक के पिता एवं जनसंघ काल के वरिष्ठ कार्यकर्ता राधेश्याम पाठक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।राधेश्याम पाठक जनसंघ काल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और आजमगढ़ से जनसंघ के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। उन्होंने संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।राधेश्याम पाठक के निधन पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह, कान्ताकर्दम, संतोष सिंह, सलिल विश्नोई, सत्यपाल सिंह सैनी, नीलम सोनकर, कमलावती सिंह, बृजबहादुर, सुनीता दयाल, दिनेश कुमार शर्मा, मानवेन्द्र सिंह, पद्म सेन चौधरी, मोहित बेनीवाल, धर्मेन्द्र सिंह, देवेश कोरी, त्रयंबक त्रिपाठी सहित अनेक पदाधिकारियों ने भी शोक व्यक्त किया।

इसके अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ल, अमर पाल मौर्य, अनूप गुप्ता, प्रियंका सिंह रावत, संजय राय, सुभाष यदुवंश, राम प्रताप सिंह चौहान, प्रदेश मंत्री शंकर गिरि, चन्द्रमोहन सिंह, मीना चौबे, अंजुला माहौर, विजय शिवहरे, शंकर लोधी, शकुन्तला चौहान, अनामिका चौधरी, पूनम बजाज, अर्चना मिश्रा साक्षी दिवाकर, आलोक वर्मा, अवनीश त्यागी, राज कुमार, अशोक तिवारी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव तथा शिव कुमार पाठक सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी राधेश्याम पाठक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

कार्यालय ग्राम पंचायत कुल्हनामऊ, विकास खण्ड–सिकरारा, जौनपुर

पत्रांक– मेमो/ग्रा0पं0वि0/ दिनांक – 03.04.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2026–27 में ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/16 वां केन्द्रीय वित्त आयोग/ग्राम स्वराज अभियान/मनरेगा/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए निम्निलिखित निर्माण सामग्रियों को क्रय करने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 06.04.2026 से 15.04.2026 तक कार्यालय कार्य दिवस में अपराह्न दो बजे तक प्रधान ग्राम पंचायत के कार्यालय पर सीलबन्द निविदा जमा कर सकते है जो दिनांक 16.04.2026 को निविदा हेतु गठित कमेटी या निर्माण समिति के सदस्यों के समक्ष प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी। निविदा फार्म पैड पर मान्य होगी।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	मात्रा	दर
1	ईंट 150 एम0एम0 प्रथम श्रेणी/एस.ओ.बी. ईट	प्रति हजार	
2	सीमेंट	प्रति बैग	
3	मोरंग बालू, महीन बालू, गंगा बालू	प्रति घन मी0	
4	स्टोन ब्लास्ट, डाला गिट्टी, पत्थर गिट्टी 20 एम.एम. से 53 एम.एम. तक ईट गिट्टी 20 एम.एम./42एम.एम.	प्रति घन मी0	
5	सरिया विभिन्न साइज	प्रति कुन्तल	
6	करकर/एसबेस्टर सीट,पैनल आयरन, समरसेबुल, बोरिंग प्लेटफार्म सहित	प्रति नग	
7	पैर्क्स ब्लाक ईट/इण्टरलाकिंग ईट/जागजेडा इण्टरलाकिंग ईट	प्रति हजार	
8	सोलर लाईट/विद्युत सामग्री/स्ट्रीट लाईट/हाइमास्क सोलर लाईट	प्रति नग	
9	शौचालय निर्माण सामग्री/पंचायत भवन निर्माण सामग्री		
10	ह्यूम पाइप 150एम.एम. 300एम.एम. 350एम.एम. 600एम.एम. 800एम.एम. NP3	प्रति मी0	
11	ढ़क्कनदार नाली निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री आवश्यकतानुसार		
12	गिट्टी की भराई, समतलीकरण का कार्य	प्रति घन मी0	
13	सफाईकर्मी स्वच्छता किट/सेनेटाइजर,डस्टबीन सहित अन्य संबंधित सामग्री	प्रति नग	
14	कटीला तार एवं ईगल/प्रिकास्ट कंकरीट बेंच	प्रति नग	
15	जिम से संबंधित सामग्री/इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री/रिबोर	प्रति नग	
16	मैदान के सुन्दरीकरण हेतु घास	प्रति धन मी0	
17	चूना, पेन्ट इत्यादि	प्रति नग	
18	वाल पेटिंग व प्रचार–प्रसार	प्रति वर्ग मी0	
19	विडियो कैमरा, दिशासूचक बोर्ड/पब्लिक अड्रेस सिस्टम,स्कूल के लिए डेक्स व बेंच।	प्रति नग	
20	गौशाला में चूना–चोकर, भूसा, मनरेगा पार्क में खेलकूद, जिम, झूला व अन्य सामग्री।		
21	हैण्डपम्प की निष्प्रयोज्य सामग्री की खुली नीलामी		

प्रतिबन्ध एवं शर्तें– सामग्री की मात्रा कार्य स्वीकृत होने के बाद निर्धारित की जायेगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी अथवा नहीं। सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि से स्वीकृत दर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा 50 रू0 के स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड भरना अनिवार्य होगा तदोपरान्त आपूर्ति किया जायेगा। सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का सेल टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तथा आयकरदाता हो प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय। प्रस्तुत दर पी.डब्लू.डी. के स्वीकृत दर से अधिक न हो। सामग्री आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा में की जानी अनिवार्य होगी। सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की दशा में भुगतान की धनराशि नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। आपूर्तिकर्ता को 4 प्रतिशत वाणिज्यकर एवं 2.24 प्रतिशत आयकर में कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/निर्माण समिति में चिह्नित होगा।

प्रधान
शिवधारी यादव

ग्राम विकास अधिकारी
प्रदीप शंकर श्रीवास्तव

वरिष्ठ पत्रकार मंजर मेहंदी किए गए सुपुर्दे खाक

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। उर्दू के जाने माने चेहरे और वरिष्ठ पत्रकार रंग कर्मी साहित्यकार रहे मंजर मेहंदी को आज वजीरगंज मौलवीबाग कब्रिस्तान में दफ्न किया गया उनकी नमाजे जनाजा इमामबाड़ा परिसर में 10 बजे अदा कराई गई जहां से उनके पार्थिव शरीर को वजीरगंज के मौलवी कब्रिस्तान में दफ्न किया गया उनके आखिरी सफर में बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाया गया ! कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष फुलावर नकवी.भदरसा नगर पालिका चेयर मैन मोहम्मद राशिद .इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर नजमुल हसन गनी. ताजिया दरान कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मुनीर आब्दी, वरिष्ठ पत्रकार अलमदार आब्दी.वसीका अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद मोहसिन.मौलाना हैदर अब्बास.मौलाना मोहम्मद आजिम बाकरी .जामा मस्जिद इमामबाड़ा के इमाम जाफर रजाद आब्दी.मौलाना नदीम रजाद जैघ्दी . सांसद प्रतिनिधि सपा नेता हामिद जाफर मीसम.सपा नेता हसन इकबाल. पूर्व सभासद वसी हैदर गुड्डू .सपा नेता सफ्फन शायरे अहले बैत चंदन सानेहाल सहित उनके अजीजो अकारिब उनके जनाजे में शामिल हुए

महाराजा निषाद राज जयंती निषाद समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में लिया हिस्सा

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। महाराजा निषाद राज जयंती के अवसर पर निषाद समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। यह शिविर निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद और अभिषेक निषाद के नेतृत्व में आयोजित किया गया। जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया।निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने बताया कि उनके आदर्श महाराजा निषादराज की जयंती के उपलक्ष्य में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि "रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है,इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए और इससे किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए।"उन्होंने आगे जानकारी दी

कि जयंती के अवसर पर अगले दिन निषादराज चौराहा (टेढ़ी बाजार) स्थित महाराजा निषादराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की।इस अवसर पर निषाद समाज सेवा ट्रस्ट के प्रबंधक एवं पूर्व जयंती अध्यक्ष रामदुलार निषाद, उपाध्यक्ष रामतिवारी निषाद, कृष्ण कुमार पांडे के विशेष सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अभिषेक निषाद, जय राज निषाद, प्रेम निषाद, सुरेश निषाद, राजबहादुर यादव, प्रदीप निषाद, मोनू कुमार, उमेश निषाद, बाबा लक्ष्मण दास, बाबा मंजीत दास, बीजेपी नेता अच्छे लाल निषाद, पूर्व प्रधान रोहित निषाद, मोहन निषाद, राजन निषाद, राहुल निषाद, हेमंत निषाद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

समाजसेवी राजन पाण्डेय ने अग्निपीड़ितों को पहुंचाई सहायता

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिले के मिल्कीपुर विधानसभा के बिसाही तथा बोडेपुर ग्रामसभा में लगी अचानक आग से 10 यादव और 1 दलित परिवार की पूरी गृहस्थी कई जानवरों के साथ जल कर खाक हो गई।जिसकी सूचना मिलते ही समाजसेवी राजन पाण्डेय ने परिवारों के मध्य पहुंचकर सभी पीड़ित परिवारों को दरी, चद्दर, कंबल तथा 500 – 500 और 1000 –1000 रूपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई।आगे भी यथासंभव हर मदद का आश्वासन देकर उनके दुखो को कम करने का प्रयास किया।समाजसेवी राजन पाण्डेय ने दूरभाष पर बताया कि अग्निकांड से प्रभावित परिवार के तन पर मौजूद कपड़े के सिवा कुछ नहीं बचता है इसलिए उनके द्वारा पिछले 20 सालों से अग्निकांडो के पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने नेताओं से अपील की है कि आप लोग भी इन लोगों की मदद के लिए आगे आयें क्योंकि इन्हीं लोगो के वोटों के बदले आप राजा बनते हैं, लेकिन मदद के बजाय आजकल के नए नेता दारु – पैसा – मुर्गा के बदले वोट लेना ज्यादा पसंद करते हैं जो की बिल्कुल गलत है।राजन पाण्डेय ने अपने विरोधियों को ललकारते हुए कहा कि जो लोग मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं कि उनके द्वारा दिए गए 1000 रुपए में क्या होता है वह लोग जाकर अग्निपीड़ित परिवार से पूछे क्योंकि परिवार को उस पैसे की वजह से 2 दिन खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती है।अग्निपीड़ित परिवारों की मदद के बाद समाजसेवी राजन पाण्डेय ने वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण पाण्डेय के परिजनों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया क्योंकि हाल में राजनारायण पाण्डेय के बड़े पिता जी का आकस्मिक निधन हो गया था।उक्त समय पर समाजसेवी राजन पाण्डेय के साथ त्रिलोकीनाथ पाण्डेय, अनिल मिश्रा, सोनू तिवारी, जिला पंचायत सदस्य अंकित पाण्डेय, बब्बू पाण्डेय, सुरेंद्र शुक्ला, सुनील मौर्य व राहुल जाटव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

अंतर्जनपदीय शातिर इनामी आरोपी को बीकापुर कोतवाली पुलिस और एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में लूट के मामले में वांछित 50 हजार रुपए के अंतर्जनपदीय इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में एसटीएफ यूनिट अयोध्या और बीकापुर कोतवाली पुलिस टीम को सफलता मिली है।लूट की घटना बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के मंगारी शुक्लहिया के सामने प्रयागराज हाईवे पर करीब से माह पूर्व 2 सितंबर 2025 की रात्रि करीब 1 बजे घटित हुई थी।बाइक सवार तीन आरोपियों द्वारा परोमा बीकापुर निवासी अमित कुमार तिवारी के साथ मारपीट करके उनकी मोटरसाइकिल, मोबाईल फोन, पर्स , आधार कार्ड, एटीएम कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस लूटकर भाग गये थे। पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध लूट की धारा में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कोतवाली पुलिस द्वारा छानबीन के दौरान अंजना चौबेपुर थाना पूरा कलंदर निवासी अवनीश कुमार चौबे, अंकित चौबे, तथा सिरसहवा थाना परशुरामपुर जिला बस्ती हाल मुकाम राम जानकी मन्दिर अमौली थाना छावनी जनपद बस्ती निवासी आर्यन उर्फ शिवम सिंह का नाम प्रकाश मे आया था।पूर्व मे अवनीश कुमार चौबे एवं अंकित चौबे को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है।आर्यन उर्फ शिवम सिंह की गिरफ्तारी के काफी प्रयास किया गया लेकिन वह पुलिस से बचता रहा। गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक अयोध्या द्वारा 50 हजार का इनाम घोषित किया गया।एसटीएफ और पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में लगी हुई थी। बताया कि आरोपी आर्यन उर्फ शिवम सिंह को एसटीएफ अयोध्या और कोतवाली बीकापुर की संयुक्त की टीम द्वारा राम जानकी मन्दिर अमौनी नहर बस्ती के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 650 रुपए बरामद किया गया है। शुक्रवार को आरोपी का चलान करके न्यायालय भेजा गया है। कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शातिर आरोपी आर्यन उर्फ शिवम सिंह के विरुद्ध जानलेवा हमला सहित अन्य गंभीर धाराओ में बस्ती, गोंडा, अयोध्या में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

जमीनी विवाद में हुई पिटाई से घायलों के परिजन से मिले विधायक

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। विकासखण्ड पूराबाजार के ग्राम रामपुर हलवारा में जमीनी विवाद को लेकर हुई पिटाई से घायल के परिजनों से मेडिकल कालेज दर्शननगर में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मुलाकात किया।सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी के साथ मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगो व परिजनों से घटना के बारें में जानकारी विधायक ने लिया। प्रकरण में घायल पक्ष को सुरक्षा देने के साथ न्यायोचित कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने सीओ को दिया। जिस पर सीओ ने मामले में अभियोग पंजीकृत होने के साथ कार्रवाई करने के बारें में विधायक को अवगत कराया।जमीनी विवाद को लेकर रामप्रकाश निषाद ने थाने पर दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि तीन अप्रैल को वह अपने पुत्रों के साथ मकान के सामने पिलर का निर्माण कर रहा था। इसी बीच अमरनाथ यादव अन्य लोगो के साथ आए व उसे निर्माण करने से मना करने लगे। रामप्रकाश का आरोप है कि जब उसने अपने घर के सामने पिलर का निर्माण होने की जानकारी दी तो अमरनाथ यादव ने अपने साथियों के साथ उसके पक्ष की लाठी–डण्डों से पिटाई शुरू कर दी। जिसमें सुनील कुमार निषाद, राज निषाद, दीपक निषाद का सिर फट गया। सभी बेहोश हो गए। जिन्हें दर्शननगर स्थित मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देशन एवं माननीय जनपद न्यायाधीशध्अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या रणंजय कुमार वर्मा की अनुमति से लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण व लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण के तहत सहायक व्यक्तियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों

के साथ बैठक की गयी।जिसमें सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या रंजिनी शुक्ला के साथ–साथ डॉ0 पवन कुमार तिवारी डी0आई0ओ0एस सर्वेश अवस्थी अध्यक्ष सी0इ0ब्ल्यू0सी0, रश्मी मिश्रा, प्रभा मणि पाल, माधुरी यादव, शशांक कुमार पाठक, राजेश कुमार गुप्ता, सौमित्र तिवारी, विशाल कुमार श्रीवास्तव, अरूण प्रकाश तिवारी, कुलशेखर सिंह, अजीज हसन, सुरभि त्रिपाठी, आदर्श श्रीवास्वत उपस्थित रहे।

पीएम की प्रेरणा से चाय बागानों के श्रमिक निकले तीर्थाटन पर,रविवार को पहले पहुंचेंगे रामनगरी

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।असम के चाय बागानों से बाहर की दुनिया देखने पहली बार तीर्थाटन के लिए निकले बागान कर्मयोगियों (श्रमिकों) की प्रथम टोली पांच अप्रैल रविवार को तड़के अयोध्या पहुंच रही है।बीते दिनों इन कर्मयोगियों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यह संभव हुआ है कि ये लोग बागानों के बाहर का संसार देखेंगे।आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने बागान में कर्मयोगियों से मिलने–जुलने के मध्य मनोहारी टी एस्टेट के प्रबंधन से कर्मयोगियों (श्रमिकों) की तीर्थयात्रा प्रायोजित करने का प्रस्ताव रखाद्य टी एस्टेट प्रबंधन व अशोक सिंघल फाउंडेशन ने इसे सहर्ष स्वीकार कियाद्यइसी क्रम में इस छोर पर अयोध्या दर्शन का दायित्व तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चम्पतराय ने स्वीकारा।तय कार्यक्रम के अनुसार मनकापुर स्टेशन से बस द्वारा कर्मयोगियों का पहला दल रविवार को कारसेवकपुरम पहुंचेगा तत्पश्चात् सभी सरयू स्नान को जाएंगे और विभिन्न मन्दिरों के दर्शन पूजन के क्रम में श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर पहुंचेंगे।दोपहर दो बजे अंगद टीला पर इनका सामाजिक सम्मेलन होगा।

बीमारी से तंग आकर बुजुर्ग ने खुद का गला रेत कर की आत्महत्या

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।थाना बाबा बाजार क्षेत्र के माँ कामाख्या चौकी बीमारी से तंग आकर बुजुर्ग ने खुद का गला रेत कर की आत्महत्या का मामला सामने आया है। सूत्र के मुताबिक मुतजहां 60 वर्षीय इंसान अली ने लंबी बीमारी से परेशान होकर आत्मघाती कदम उठा लिया।बताया जा रहा है कि वे पिछले करीब एक वर्ष से पूरे शरीर में असहनीय जलन की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके चलते मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गए थे। परिजनों के अनुसार इससे पहले भी वह एक–दो बार फांसी लगाकर जान देने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन समय रहते उन्हें रोक लिया गया था। इस बार उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच गए तथा फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

'ढीले बिजली तार से शॉर्ट सर्किट, आग में जलकर खाक हुई गेहूं की फसल'

ब्यूरो चीफ

आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर । तहसील क्षेत्र के गौरा–बरामऊ गांव के पूरे बरवन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने किसान की पकी हुई गेहूं की फसल को पल भर में राख कर दिया। इस घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ और कड़ी मेहनत से आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे आसपास की अन्य फसलें बच गईं। जानकारी के अनुसार गांव निवासी राकेश यादव के खेत के ऊपर से गुजर रही 11000 वोल्ट की बिजली लाइन के ढीले तार आपस में टकरा गए, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि तार काफी समय से ढीले और जर्जर हालत में लटक रहे हैं। बताया गया कि एक कौवा तार पर बैठा, जिससे दोनों तार आपस

में टकरा गए और निकली चिंगारी से खेत में खड़ी पकी हुई गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तेज रूप ले लिया और लगभग एक बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई।राजस्व टीम से लेखपाल अमित यादव मौके पर पहुंच कर नुकसान का आंकलन कर रहे है। ग्रामीण शिव कुमार मिश्रा ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब से यह लाइन डाली गई है, तभी से तार और खंभे जर्जर हालत में हैं। तेज हवा या पक्षियों के बैठने पर तार अक्सर आपस में टकरा जाते हैं और इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन काफी देर तक दमकल वाहन मौके पर नहीं पहुंच सका। अंततः ग्रामीणों ने ही कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि जर्जर बिजली तारों को जल्द ठीक कराया जाए, ताकि भविष्य में किसानों को ऐसे नुकसान से बचाया जा सके। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सल्लू भी मौके पर मौजूद है।

एडीजी प्रवीण कुमार ने रौनाही थाना से सम्बंधित हर पहलुओं का किया निरीक्षण

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। थाना रौनाही का मुआयना करने के लिए शुक्रवार को रात एडीजी जोन प्रवीण कुमार रौनाही थाने पहुंचे।इस मौके पर अधिकारियों ने एडीजी प्रवीण कुमार का स्वागत किया।उसके बाद निरीक्षण के दौरान

उन्होंने साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क,मिशन शक्ति केंद्र और कार्यालय के रख–रखाव का निरीक्षण कर सजा कर रखे गए असलहों के बारे में जानकारी ली।साथ ही थाना परिसर सहित मेस का भी निरीक्षण किया। सवाल जवाब के जरिए बुद्धि को परखा और क्रमबद्ध खड़े हुए उप निरीक्षक, सिपाही, महिला कांस्टेबल सहित मातहतों से परिचय लिया और सम्बंधितो से जानकारी लेते हुए उन्हें उपयुक्त दिशा निर्देश दिया। एडीजी जोन प्रवीण कुमार रौनाही थाने में निरीक्षण के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट नजर आए। इस अवसर पर डीआईजी सोमेन वर्मा, वरिष्ठ पुलिसअधीक्षक डा.गौरव ग्रोवर, एस पी ग्रामीण बलवंत चौधरी, रौनाही थाना प्रभारी लालचन्द सरोज, इंस्पेक्टर क्राइम अब्दुल रहमान खान सहित जोन के अधिकारी मौजूद रहे।

गोसाईगंज थाना प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मी निलंबित

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के आरोप में गोसाईगंज थाना प्रभारी शारदेन्दु दुबे और आरक्षी अजय यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।मिली जानकारी के अनुसार, ड्यूटी के दौरान लापरवाही की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया।एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

जिलाधिकारी ने नगर निगम के विभिन्न निर्माण कार्यो का किया निरीक्षण

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी के साथ नगर निगम अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। गांधी भवन प्रेक्षागृह गांधी भवन प्रेक्षागृह का निरीक्षण किया गया। भवन को रंगमंच आदि के उपयोग हेतु तैयार किया जा रहा है। इसमें एक यू–ट्यूब स्टूडियो एवं ई–लाईब्रेरी का भी निर्माण किया जा रहा है। यह सभी 30 जून, 2026 तक जनता के उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाएगा।

'प्लेनेटोरियम एवं मल्टी लेबल पार्किंग' शहरवासियों की सुविधा एवं बच्चों के बौद्धिक विकास के लिये प्लेनेटोरियम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिये विज्ञान प्रदर्शिनी आदि बनाई जा रही है। इस प्लेनेटोरियम से बच्चों में वैज्ञानिक सोच एवं बौद्धिक विकास के साथ–साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित होगी। इसके अतिरिक्त मल्टीलेबल कार पार्किंग से यहां को लोगों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त होगी। यह कार्य 02 अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सीएम0 ग्रिड (तेल टंकी रोड) सीएम0 ग्रिड (तेल टंकी रोड) का निरीक्षण किया गया। यह कार्य अपने अंतिम चरण में है तथा यह कार्य इसी माह अप्रैल के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। शहर में पहली बार बिजली एवं अन्य तारों को अण्डरग्राउण्ड डाला गया है। यह सुन्दर सड़क चौड़े फुट–पाथ और सुन्दर लाईटिंग के साथ उपलब्ध होगी। इसी सड़क का विस्तार लाल इमली चौराहा, पंखी चौराहा, सदर बाजार थाना होते हुये श उद्यान तक किया जाएगा।

'हॉकी फील्ड'

हॉकी फील्ड का निरीक्षण किया गया। हॉकी फील्ड का कार्य दिसम्बर–2026 तक पूर्ण हो जाएगा। ऑस्टोटर्फ तथा फ्लड लाईट्स के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैदान शहरवासियों को उपलब्ध होगा, जिसमें रात्रि में भी खेला जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इसके निकट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा है तथा सीनियर केयर सेंटर का निर्माण भी इसके निकट चल रहा है। इनसे शहरवासी लाभान्वित होंगे।

'नगर निगम का नवीन कार्यालय भवन'

नगर निगम के कार्यालय के निर्माणाधीन नवीन भवन का निरीक्षण किया गया। यह भवन इस माह के अन्त तक नये नगर निगम कार्यालय के लिये उपलब्ध होगा। साथ ही साथ इसके निकट बन रहे 1500 व्यक्तियों की क्षमता के कन्वेंशन सेंटर एवं 40 दुकानों से युक्त अर्बन फूड प्लाजा तथा इसमें ओपन एयर थियेटर भी उपलब्ध होगा।

'केरुगंज से मघईटोला होते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग तक स्मार्ट सिटर रोड'

केरुगंज से मघईटोला होते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग तक स्मार्ट सिटर रोड का निरीक्षण किया गया। इस मार्ग से अतिक्रमण को हटाये जाने तथा तेजी से कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये।

गर्रा नदी के पुल को उठाये जाने एवं बाढ़ से बचाव हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर 03 बॉक्स (कल्वर्ट) का कार्य–

गर्रा नदी के पुल को उठाये जाने का कार्य का निरीक्षण किया गया। उक्त के सम्बन्ध में सेतु निगम के अधिकारियों को कार्य शीघ्रता से अधिक से अधिक कार्मिकों की टीमे लगा कर कराये के निर्देश दिये गये। इसी के साथ शहर को बाढ़ से बचाये जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर चांदापुर चौराहे पर नहर के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। इस कार्य को तेजी से कराते हुये आगामी बाढ़ की सम्भावना के दृष्टिगत शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीताल ढाबे के पास तथा इसके आगे 03 बड़े बॉक्स (कल्वर्ट) बनाये जाने के

सर्किट हाउस

सर्किट हाउस के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य को तेजी से कराये जाने के निर्देश दिये गये।

'चांदापुर चौराहे पर नहर के चौड़ीकरण का कार्य'

निरीक्षण के दौरान शहर को बाढ़ से बचाये जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर चांदापुर चौराहे पर नहर के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। इस कार्य को तेजी से कराते हुये आगामी बाढ़ की सम्भावना के दृष्टिगत शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त एसके सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।